



कर्ज का भार बढ़ायेगा यह बजट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना दूसरा बजट सदन में रखा है। वर्ष 2024-25 के इस बजट का आकार 58444 करोड़ है। इसमें मुख्यमंत्री ने सात नयी योजनाएं और तीन नयी नीतियां लाने की घोषणा की है। 58444 करोड़ के इस बजट में 42153 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां और 46667 करोड़ राजस्व व्यय होने का अनुमान है। वर्ष के अन्त में राजकोषीय घाटा 10784 करोड़ रहने का अनुमान है। इसके खर्च का ब्योरा इस प्रकार रहने वाला है। 100 रुपये के कुल खर्च में 25 रुपये वेतन पर 17 रुपये पेंशन, ब्याज अदायगी पर 11 रुपये, ऋण की वापसी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट पर 10 रुपये, 28 रुपये पूंजीगत कार्यों पर खर्च होंगे। 42153 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां में राज्य से 18739.39 करोड़, केंद्रीय प्राप्तियां से 18141.47 करोड़, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अनुदान से 5272.22 करोड़ प्राप्त होंगे। पूंजीगत प्राप्तियां 12786.66 करोड़ होंगी। जिसमें 12759.11 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण होगा। राज्य का कुल राजस्व 15100.69 करोड़ और गैर राजस्व 3638.70 करोड़ रहेगा। पिछले वर्ष का राजस्व 13025.97 करोड़ और गैर कर राजस्व 3447.01 करोड़ था। इस तरह पिछले वर्ष के मुकाबले 2266.61 करोड़ का कर और गैर कर राजस्व इस वर्ष बढ़ा है। यह बढ़ौतरी वर्ष में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के दामों में की गयी वृद्धि का परिणाम है।

वर्ष 2023-24 के लिए जो 10307.59 करोड़ की अनुपूरक मांगे लायी गयी है उसके बाद वर्ष का राजस्व घाटा 5480 करोड़ रहने का अनुमान है। जबकि 2023-24 के बजट अनुमान सदन में रखते हुये यह घाटा 4704.12 करोड़ रहने का अनुमान था और राजकोषीय घाटा 9900.14 करोड़ आंका गया था। इस वर्ष का विकासात्मक बजट

- “28 पैसे विकास के लिये” के अनुसार 163 64.3 2 करोड़ का प्रावधान चाहिये था।
- लेकिन विकासात्मक बजट केवल 9989.49 करोड़ ही रखा गया है।
- जब वेतन पर पिछले वर्ष के मुकाबले कम प्रावधान है तो नयी सरकारी नौकरियां कैसे संभव होगी?

9989.49 करोड़ रखा गया है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक 2022-23 का सकल ऋण 76650.70 करोड़ दिखाया गया है। वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में रख दिया गया है। जिसके मुताबिक प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 आंकी गयी है। इसी तरह प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा 1,18,000 रुपये हैं। पिछले

वर्ष वेतन पर खर्च 26.40 खर्च रखा गया था जो इस बार 25 रह गया। मुख्यमंत्री के बजट भाषण के अनुसार 28 पैसे पूंजीगतकार्यों पर खर्च होंगे। पूंजीगत खर्च विकासात्मक खर्च माना जाता है। 28 पैसे विकास पर खर्च होने का अर्थ है की 58,444 करोड़ में से 16,364.32 करोड़ विकास पर खर्च होने चाहिये जबकि विकासात्मक

बजट केवल 9989.49 करोड़ है। यह अन्तर क्यों है इसकी कोई व्याख्या दस्तावेजों में नहीं है।

बजट के इन आंकड़ों के परिदृश्य में यदि मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं को देखा जाये तो यह लगता है कि बजट तैयार करने वालों ने घोषणाएं तो करवा दी हैं लेकिन उनका पूरा करने के सक्षम बजट प्रावधान नहीं रखे गये हैं।

सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि उसे हर माह एक हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। और इसके लिये वाकायदा आरटीआई के माध्यम से आंकड़े जारी करके इसको प्रमाणित भी किया गया है लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले जब इस वर्ष वेतन अदायगी के लिये कम प्रावधान किया गया है तो क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि इस वर्ष में सरकार नयी नौकरियां नहीं दे पायेगी। बजट दस्तावेजों के मुताबिक 72 पैसे प्रतिबद्ध खर्चों के लिये हैं और 28 पैसे विकास के लिये के अनुसार 16364.32 करोड़ होनी चाहिये थे लेकिन विकास के लिये तो बजट में केवल 9989.49 करोड़ का ही प्रावधान है। क्या इस अंतर को कर्ज लेकर पूरा किया जायेगा? इसी तरह बजट दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इससे कर्ज का भार और बढ़ेगा।

II. बजट को समझने के लिए मुख्य संकेतक				
(₹ करोड़ों में)				
	वास्तविक 2022-23	बजट अनुमान 2023-24	बजट अनुमान 2024-25	
क. राजस्व प्राप्तियां				
(i) राज्य प्राप्तियां	13469.92	16472.98	18739.39	
(ii) केन्द्रीय प्राप्तियां (including Central Taxes) of which	20468.44	18130.95	18141.47	
(a) केन्द्रीय करों में हिस्सा	7883.98	8478.02	10124.20	
(b) केन्द्रीय हस्तांतरण	12584.46	9652.93	8017.27	
(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अनुदान (excluding CSS Loans)	4151.14	3395.94	5272.22	
योग (राजस्व प्राप्तियां)	38089.50	37999.87	42153.08	
ख. राजस्व व्यय				
(i) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	3190.03	2915.78	3878.27	
(ii) राज्य स्कीमें	41235.23	39788.22	42788.36	
योग (राजस्व व्यय)	44425.26	42704.00	46666.63	
निवल (राजस्व घाटा/ लाभ)*	-6335.76	-4704.12	-4513.55	
ग. पूंजीगत प्राप्तियां				
(i) सकल ऋण (excluding W&M / overdraft but includes net PF receipts)	16260.94	11839.64	12759.11	
(ii) ऋणों की वसूलियां	82.79	26.07	27.55	
(iii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	12.59	0.00	0	
योग (पूंजीगत प्राप्तियां)	16356.33	11865.71	12786.66	
घ. पूंजीगत व्यय				
(i) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	879.95	480.91	1401.98	
(ii) राज्य स्कीमें	8608.47	8227.81	8875.00	
(क) ऋणों की अदायगियां	3348.96	3486.64	3979.11	
(ख) पूंजीगत परिव्यय	5154.21	4721.48	4867.72	
(ग) अन्य	105.30	19.69	28.18	
योग पूंजीगत व्यय	9488.42	8708.72	10276.98	
राजकोषीय अधिशेष/घाटा*	-12379.84	-9900.14	-10783.87	
*अधिशेष(+)/घाटा(-)				

IV. व्यय का विश्लेषण						
राज्य के व्यय का मानकवार विवरण कुल व्यय में प्रत्येक मानक के प्रतिशत हिस्से सहित नीचे दर्शाया गया है:						
कुल व्यय में प्रतिशतता के रूप में मानकवार व्यय का विवरण						
(₹ करोड़ों में)						
	वास्तविक 2022-23	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2023-24	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2024-25	कुल का प्रतिशत
क. मानकवार विवरण	58234.95	97.59	52324.67	97.96	57163.63	97.81
1. वेतन	14149.32	23.31	14099.52	26.40	14687.51	25.13
2. मजदूरी	275.84	0.45	246.07	0.46	278.46	0.48
3. सहायता अनुदान (वेतन)	1736.31	2.86	1798.58	3.37	2280.90	3.90
4. सहायता अनुदान (अवेतन)	2734.01	4.50	2335.68	4.37	3001.10	5.14
5. सहायता अनुदान (पूँजी परिसम्पत्तियां)	1376.62	2.27	779.97	1.46	798.54	1.37
6. पेंशन	9283.87	15.29	8693.78	16.28	9961.10	17.04
7. ब्याज	4828.64	7.95	5562.01	10.41	6255.34	10.70
8. रख रखाव	2235.32	3.68	2774.88	5.20	2739.56	4.69
9. मुख्य निर्माण कार्य	5310.29	8.75	4726.58	8.85	5782.31	9.89
10. निवेश	423.04	0.70	228.11	0.43	175.95	0.30
11. ऋण	10246.27	16.88	5506.35	10.31	5507.30	9.42
12. उपदान	1973.32	3.25	1244.28	2.33	1188.62	2.03
13. सामाजिक सुरक्षा पेंशन	1150.48	1.90	1266.77	2.37	1438.48	2.46
14. विद्युत् प्रभार	475.92	0.78	474.05	0.89	507.23	0.87
15. अन्य प्रभार	1881.44	3.10	1429.50	2.68	1463.02	2.50
16. सामग्री एवं सम्भरण	466.35	0.77	428.88	0.80	430.60	0.74
17. मानदेय	471.48	0.78	529.66	0.99	577.09	0.99
18. मशीनरी एवं औजार	216.44	0.36	200.01	0.37	90.50	0.15
ख. स्थापना सम्बन्धित	717.82	1.18	647.46	1.21	670.97	1.15
(क) यात्रा व्यय	42.99	0.07	40.71	0.08	40.51	0.07
(ख) कार्यालय व्यय	200.78	0.33	158.67	0.30	164.91	0.28
(ग) मोटर वाहन (बाह्य स्रोत वाहन/पेट्रोल/मरम्मत)	77.63	0.13	51.66	0.10	70.90	0.12
(घ) चिकित्सा प्रवृत्ति	179.36	0.30	179.75	0.34	178.15	0.30
(ङ) आउटसोर्सिंग प्रभार	181.19	0.30	167.71	0.31	171.62	0.29
(च) अन्य	35.87	0.06	48.97	0.09	44.88	0.08
ग. अन्य	747.73	1.23	440.60	0.82	609.01	1.04
योग (क+ख+ग):	60700.51	100.00	53412.72	100.00	58443.61	100.00

राज्यपाल ने बिलासपुर के डोहकेश्वर धाम में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में स्थित डोहकेश्वर धाम में 36 देवी-देवताओं की प्रतिमा



की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भाग लिया। उन्होंने दो वर्षों की काम अवधि में बन कर तैयार हुए डोहकेश्वर धाम का लोकार्पण भी किया।

राज्यपाल ने कहा कि डोहकेश्वर धाम के निर्माण से आस्था, संस्कृति और धरोहर का पोषण होगा और इससे यहां धार्मिक पर्यटन तथा आर्थिक

गतिविधियां भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि भावड़ा बांध के निर्माण के कारण यह क्षेत्र भी उजड़ गया था और मंदिर पानी में डूब गए थे। लेकिन, आज यहां

देवभूमि है और यहां के लोगों को भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रयास करने चाहिये। उन्होंने कहा कि डोहकेश्वर धाम में हर व्यक्ति को योगदान देकर इस स्थान को अद्वितीय बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस स्थान का प्रचार-प्रसार भी होना जिससे यहां की दिव्यता और बढ़ जाएगी।

बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के प्रयासों पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम एक व्यक्ति को भी नशे से दूर कर सकेंगे तो यह स्वस्थ समाज की दिशा में हमारा अमूल्य योगदान होगा। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर नशामुक्ति के लिये अभियान चलाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे इस देवभूमि की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी।

राज्यपाल ने इस अवसर पर मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमजीवियों को सम्मानित भी किया। स्थानीय विधायक जीतराम कटवाल ने क्षेत्र में किये गए विकास कार्यों की जानकारी दी। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने राज्यपाल तथा लेडी गवर्नर को सम्मानित किया।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल

मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया किसान हितैषी बजट:नरेश चौहान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा बजट दूरदर्शी, नवोन्मेषी एवं किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि विकट वित्तीय स्थितियों के बावजूद बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए समाज में पंक्ति के अन्तिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का प्रयास झलकता है।

बजट को किसानों का हितैषी करार देते हुए नरेश चौहान ने कहा कि यह बजट ग्रामीण हिमाचल की समृद्धि सुनिश्चित करेगा और किसान व बागवानों को इससे बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए इसे स्वरोजगार से

जोड़ने की पहल के दृष्टिगत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना के तृतीय चरण में कई उपाय प्रस्तावित हैं। यह मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के अनुरूप है जिन्होंने युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 680 करोड़ रुपये की यह योजना आरम्भ की है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ ही बड़े स्तर पर कृषक वर्ग रसायनमुक्त खेती के प्रति प्रोत्साहित होगा।

उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में 12 करोड़ रुपये की लागत से एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित होने से यह बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता, दक्षता, पर्यटन और विपणन से संबंधित बागवानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिगत एक संसाधन केन्द्र

के रूप में कार्य करेगा।

बजट में घोषित डिजिटल मीडिया पॉलिसी-2024 की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय वेब



पोर्टल और चैनलों को सहयोग के साथ ही प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक गतिविधियों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित होगा।

अर्की क्षेत्र के 71 गांव के लिए वरदान सिद्ध होगी नवगांव खड्ड पर निर्माणाधीन योजना

शिमला/शैल। सोलन जिला के अर्की उपमण्डल में लगभग 06 करोड़ रुपए की लागत से नवगांव खड्ड पर निर्माणाधीन पेयजल आपूर्ति योजना क्षेत्र की 08 ग्राम पंचायतों के लिए वरदान सिद्ध होगी। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कश्लोग, सेवड़ा चण्डी, पारनू, संघोई, मांगू, गियाणा, नवगांव और दाड़लाघाट के निवासियों को यह पेयजल आपूर्ति योजना पानी की कमी से छुटकारा दिलाएगी। इस परियोजना से इन 08 ग्राम पंचायतों के 71 गांवों के लगभग 09 हजार लोग लाभान्वित होंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि नवगांव खड्ड पर निर्माणाधीन इस पेयजल आपूर्ति योजना से बिलासपुर जिला की जलापूर्ति योजनाओं पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर नवगांव खड्ड में जल बहाव का वैज्ञानिक पद्धति से गणितीय आकलन किया गया है। जिसमें यह पाया गया कि यदि वर्तमान समय के अनुरूप चार से पांच माह तक बारिश न हो तो भी इस खड्ड में नीचे की ओर जल बहाव लगभग 380 एलपीएस पाया गया है, जबकि इस निर्माणाधीन योजना के लिए जल मांग

केवल 10.53 एलपीएस है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन योजना के बिन्दु तक कुल जलग्रहण क्षेत्र का लगभग 89 प्रतिशत सोलन जिला में है। उन्होंने कहा कि नवगांव खड्ड में समुचित जल उपलब्धता के अनुरूप ही अर्की विधानसभा क्षेत्र की 08 ग्राम पंचायतों के 71 गांवों के लिए पेयजल योजना निर्मित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना से इन 08 ग्राम पंचायतों के निवासियों को लाभान्वित किया जाएगा और किसी अन्य इकाई को इस योजना से जलापूर्ति नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ शरारती तत्वों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जोकि पूरी तरह से तथ्यहीन व आधारहीन है। उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्ण रूप से सोलन जिला में निर्मित की जा रही है और इससे जल स्रोत एवं उस पर निर्भर अन्य जनसंख्या को कोई हानि नहीं होगी। ऐसे में लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना के सम्बन्ध में विभिन्न शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण समिति गठित की गयी थी। इस समिति में जल शक्ति

वृत्त सोलन और बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता तथा जल शक्ति मण्डल बिलासपुर एवं अर्की के अधिशाषी अभियंता शामिल थे। इस समिति ने सभी पहलुओं का गहन निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इस परियोजना के निर्माण से जल बहाव क्षेत्र के नीचे स्थित योजनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संदर्भ में जल शक्ति विभाग की भू-जल सेल के वरिष्ठ जल भूविज्ञानी ने भी योजना स्थल के निरीक्षण के उपरांत स्पष्ट किया है कि नवगांव खड्ड पर इस पेयजल योजना के निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पेयजल मूलभूत आवश्यकता है और सरकार द्वारा सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

संयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री के घर पहुंच कर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ऊना जिला के गोंदपुर जयचंद स्थित उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पैतृक निवास पहुंचे और उनकी धर्मपत्नी प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।



इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री का अकस्मात निधन न केवल परिवारजनों बल्कि इस क्षेत्र व पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि दिवंगत सिम्मी अग्निहोत्री सामाजिक कार्यों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थीं तथा जरूरतमंदों

की मदद के लिए सदैव तत्पर रहती थीं। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला ऊना के हरोली से शुरू किये गये विशेष जागरूकता अभियान में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा

की शांति व शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, उपायुक्त जतिन लाल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

राज्यपाल के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राजभवन के कर्मचारियों ने बधाई दी

शिमला/शैल। शिव प्रताप शुक्ल का हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राजभवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजभवन

का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका एक वर्ष का कार्यकाल संतोषजनक रहा।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने राज्यपाल को



के अधिकारियों व कर्मचारियों ने राज्यपाल को बधाई दी। लेडी गवर्नर एवं राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष जानकी शुक्ल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं।

राजभवन के स्टाफ से संवाद करते हुए राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और सहभागिता के लिये प्रदेशवासियों

बधाई देते हुए उनके द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों की जानकारी और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने इस अवधि के दौरान प्रदेश के विकास के लिए राज्यपाल द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

सरकार के एजेंडे से मजदूर कर्मचारी गायब: विजेंद्र मेहरा

शिमला/शैल। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि हिमाचल सरकार का बजट मजदूरों कर्मचारियों की आकांक्षाओं के खिलाफ है। आत्मनिर्भर हिमाचल के दस मुख्य बिंदुओं वाले बजट में मजदूरों कर्मचारियों की बात तक न करना ही बजट की दिशा को बताता है। सरकार के एजेंडे से मजदूर कर्मचारी गायब हैं। भारी महंगाई के दौर में मजदूरों की दिहाड़ी में केवल 25 रुपये की बढ़ोतरी करना, मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम वेतन न देना, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा कर्मियों को ग्रेजुटी व न्यूनतम वेतन सुविधा लागू न करना, वाटर कैरियर, जल रक्षकों, मस्टी परपज वर्करज, पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटरों, चौकीदारों, राजस्व चौकीदारों, पंचायत वेटनरी असिस्टेंट के

मासिक वेतन में केवल 300 से 500 रुपये बढ़ोतरी करना व उन्हें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन न देना उनके साथ क्रूर मज़ाक है। आउटसोर्स कर्मियों, सिलाई अध्यापकों, एसएमसी अध्यापकों, आईटी टीचर्स व एसपीओ के वेतन में नाम मात्र बढ़ोतरी करना व उनके लिये सरकार द्वारा कोई ठोस नीति न बनाना बेहद चिंताजनक है। औद्योगिक मजदूरों की 40 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी, श्रम कानूनों की पालना, उनके एसओपी व सुरक्षा नियमों पर यह बजट खामोश है। निगमों व बोर्डों की ओपीएस बहाली पर खामोशी खलने वाली है व सरकार की दस गारंटियों की वादा खिलाफी है। यह बजट मजदूरों कर्मचारियों के दुखों का निवारण करने वाला बजट नहीं है।

हिमाचल को उसके अधिकार मिलने चाहिए: मुख्यमंत्री यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था होने से बागवानों में खुशी की लहर: राठौर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक निजी न्यूज चैनल के 'मंच' कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि छोटे राज्यों के हकों को दबाया नहीं जाना चाहिए और हिमाचल को उसके अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बावजूद बीबीएमबी में हिमाचल के हक नहीं मिल रहे हैं तथा पंजाब व हरियाणा को छोटे भाई हिमाचल का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किशाऊ जल विद्युत परियोजना में वाटर कम्पोनेंट आधार पर पावर कम्पोनेंट में 90:10 केन्द्र तथा राज्य सरकार को फंड करने अथवा राज्य के हिस्से में सभी पावर कम्पोनेंट में 50 वर्ष तक ब्याजमुक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध भी केन्द्र से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में

श्रीराम मंदिर निर्माण की सभी को खुशी है लेकिन इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भगवान राम सभी के आराध्य हैं और सरकारें उनके आदर्शों पर चले। उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पर केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की, जबकि प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में पूरे दिन का अवकाश घोषित किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेला। वर्तमान सरकार ने अपने 14 माह के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए, जिससे धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का बजट प्रदेश को समृद्धि व खुशहाली की राह पर ले जाने की उसकी सोच को दर्शाता है। वर्तमान

राज्य सरकार ने पहले ही बजट में प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों व जलवायु के अनुरूप हरित उद्योगों को प्रोत्साहन के दृष्टिगत अनेक प्रावधान किए। राज्य सरकार ई-वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है और ई-टैक्सी की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हिमाचल में छह ग्रीन कोरिडोर बनाए जा रहे हैं और चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली बरसात में प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी तबाही देखी है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ व भुज त्रासदी के दौरान केंद्र सरकार ने विशेष राहत पैकेज दिया, लेकिन हिमाचल में आयी इस आपदा पर राज्य को कोई भी विशेष मदद प्रदान नहीं की गई, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है।

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता व



ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि सेब बिक्री के लिए यूनिवर्सल कार्टन की घोषणा ऐतिहासिक है। बागवान पिछले कई सालों से इसकी मांग कर रहे थे। उन्होंने खुद इस मामले को कई मर्तबा विधानसभा में उठाया है। राठौर ने

कहा कि कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा की है जिसका वह पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ किसान व बागवानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रावधान बजट में किये गये हैं। सरकार ने नई योजनाएं भी शुरू की है ताकि प्रदेश का विकास हो सके।

4 प्रतिशत डीए व 1 मार्च से देय एरियर की घोषणा से कर्मचारियों को राहत मिली है। एसएमसी अध्यापक और कंप्यूटर अध्यापकों के लिए 1900 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। मनरेगा की दिहाड़ी 240 से 300 करना सरकार का सराहनीय कदम है। गरीब बच्चों के लिए सुख शिक्षा योजना एक बड़ा कदम है जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की सरकार ने घोषणा की है। गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए 3 लाख तक आर्थिक सहायता ऐतिहासिक कदम है।

चिकित्सा अधिकारियों की मांगों और शिकायतों के निवारण के लिए समिति गठित: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में चिकित्सा अधिकारियों की शिकायतों और मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति में निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निदेशक चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह समिति चिकित्सकों की पदोन्नति से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और चिकित्सा अधिकारियों के कल्याण के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकट वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार चिकित्सकों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य

की अर्थव्यवस्था अब धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य के कर्मचारियों को समय पर सभी आर्थिक लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों का आहवान किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में वे प्रदेश सरकार को यथासम्भव सहयोग प्रदान करें।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार नए चिकित्सा अधिकारियों और सहायक स्टाफ की भर्ती कर रही है। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के कार्य को बेहतर बनाने के लिए आठ घंटे की शिफ्ट शुरू करने पर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और उनके कौशल उन्नयन के लिए चिकित्सकों

के लिए विदेशों के एक्सपोजर टूर भी आयोजित करवाए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सकों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों के डाटा को डिजिटल बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं घर के समीप उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर, प्रत्येक संस्थान में 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा रहे हैं।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्मल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, विशेष सचिव स्वास्थ्य नीरज कुमार और डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी और चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार समाज के जरूरतमंद व वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एकल नारी संगठन के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के जरूरतमंद व वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा महिलाओं के 27 वर्ष आयु तक के बच्चों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि



सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करते हुए 40 हजार नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए लगभग 1260 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे वृद्ध, विधवा, एकल नारी, दिव्यांगजन और कुष्ठ रोगी सहित लगभग 7 लाख 84 हजार लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

यह योजना नर्सिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों इत्यादि में उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर होने वाले व्यय को वहन करेगी। इसके अतिरिक्त पात्र बच्चों को एक हजार रुपये प्रतिमाह उनके आवर्ती जमा खातों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जमा

किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पात्र महिलाओं को वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के अंतर्गत लाते हुए इस पर लगभग 41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विधवा महिलाओं को गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाएगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत नवनिर्मित घरों के लिए बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का भी प्रावधान किया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत सोलन जिला के कण्डाघाट में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में 27 वर्ष आयु तक के दिव्यांगजनों को खेल मैदान, आवासीय परिसर सहित अन्य विविध सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त जिन पात्र दिव्यांग बच्चों के पास रहने की कोई सुविधा नहीं है, उन्हें किराए पर आवास के लिए वित्तीय मदद भी प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्थन, उपायुक्त अनुपम कश्यप सहित एकल नारी संगठन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में लगेगी विकासात्मक प्रदर्शनी

शिमला/शैल। मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव-2024 के अवसर पर पड़ल मैदान में विभिन्न विभागों की विकासात्मक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी को लेकर पड़ल मैदान में विभागों को स्टॉल आबंटित करने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने स्टॉल आबंटन उपसमिति की बैठक ली। जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक में एडीएम ने अधिकारियों को मेले में विभागीय प्रदर्शनी लगाने के संबंध में स्थान की आवश्यकता को लेकर 26 फरवरी तक अवगत कराने के निर्देश दिए ताकि समय रहते स्टॉल आबंटन की उचित व्यवस्था की जा सके।

डॉ. मदन कुमार ने कहा कि मेले में पड़ल में विभागों की विकासात्मक गतिविधियों की प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को सरकार के जनहित के कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। उन्हें

योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाएगा, जिससे लोगों की मदद होगी।

एडीएम ने निर्देश दिए कि जिन विभागों तथा संगठनों की शिवरात्रि महोत्सव-2023 में आबंटित स्टॉल की अदायगी शेष है, वे जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्हें पुरानी राशि के भुगतान के बाद ही इस बार महोत्सव में दिये जाएंगे।

उन्होंने बैठक में नगर निगम के अधिकारियों को मेले के दौरान आयोजन स्थल पर साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराने को भी कहा। उन्होंने महोत्सव के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाये रखने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। उन्होंने मेला स्थल पर पानी की उचित निकासी के लिए भी आवश्यक पग उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत अधिकारी अचिंत डोगरा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में हिमाचल पुलिस के जवानों को पहले दो स्थान हासिल

शिमला/शैल। लखनऊ में आयोजित हो रही 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान 14 फरवरी, 2024 को ऑफिस

यह मीट रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा 12 फरवरी से 16 फरवरी, 2024 तक आयोजित की जा रही है। पूरे भारत में 36 लाख से अधिक



ऑटोमेशन (इवेंट-2) में हिमाचल प्रदेश पुलिस के 6वीं आईआरबीएन के आरक्षी विजय कुमार, नंबर 731 ने प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर अवेयरनेस (इवेंट-2) में एचपीआईपीएस पीटीसी डरोह के आरक्षी अमन कुमार ने दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक हासिल किया।

पुलिस कर्मी कार्यरत हैं। ऑल इंडिया ड्यूटी मीट प्रतियोगिताओं में हिमाचल प्रदेश पुलिस 161.88 अंकों के साथ पहले स्थान पर चल रहा है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोनों पुलिस कर्मियों को उनकी सराहनीय उपलब्धियों और प्रदेश तथा पुलिस विभाग का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी है।

एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

गंभीर होंगे किसान आन्दोलन के परिणाम



किसान फिर आन्दोलन पर हैं। इससे पहले भी तीन कृषि कानूनों के विरोध में एक वर्ष भर किसान आन्दोलन पर रहे हैं। यह आन्दोलन तब समाप्त हुआ था जब प्रधानमंत्री ने यह कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसान तब तक आन्दोलन नहीं छोड़ता जब तक उसकी मांगें मान ली जाती हैं। इसलिये

अब भी किसान अपनी मांग पूरी करवा कर ही आन्दोलन समाप्त करेंगे। पिछले आन्दोलन को दबाने, असफल बनाने के लिये जो कुछ सरकार ने किया था वही सब कुछ अब किया जा रहा है और किसान न तब डरा था और न ही अब डरेगा। इसलिये यह समझना आवश्यक हो जाता है कि किसानों की मांगें हैं क्या और कितनी जायज हैं। जब सरकार तीन कृषि विधेयक लायी थी तब कारपोरेट जगत के हवाले कृषि और किसान को करने की मंशा उसके पीछे थी। जैसे ही किसानों को यह मंशा स्पष्ट हुई तो वह सड़कों पर आ गया और उसका परिणाम देश के सामने है। इस वस्तुस्थिति में वर्तमान आन्दोलन को देखने समझने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र का जीडीपी और रोजगार में सबसे बड़ा योगदान है। यह सरकार की हर रिपोर्ट स्वीकारती है। लेकिन इसी के साथ यह कड़वा सच है कि देश में होने वाली आत्महत्या में भी सबसे बड़ा आंकड़ा किसान का ही है। ऐसे में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि जो अन्नदाता है और जिसकी भागीदारी जीडीपी और रोजगार में सबसे ज्यादा है वह आत्महत्या के कगार पर क्यों पहुंचता जा रहा है। स्वभाविक है कि सरकार की नीतियों और किसान बागवान की व्यवहारिक स्थिति में तालमेल नहीं है। आज सरकार का जितना ध्यान और योगदान कारपोरेट उद्योग की ओर है उसका चौथा हिस्सा भी किसान और किसानों के कोर सैक्टर की ओर नहीं है। कोरोना काल के लॉकडाउन में जहां उद्योग जगत प्रभावित हुआ वहीं पर किसान और उसकी किसानी भी प्रभावित हुई। कारपोरेट जगत को उभारने के लिये सरकार पैकेज लेकर आयी लेकिन कृषि क्षेत्र के लिये ऐसा कुछ नहीं हुआ। कारपोरेट घरानों का लाखों करोड़ों का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। आज जब सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी चन्दा बाण्ड योजना को असंवैधानिक करार देकर इस पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाते हुये चन्दा देने वालों की सूची तलब कर ली है तब यह सामने आया है कि विजय माल्या ने विदेश भागने से पहले 10 करोड़ का चन्दा भाजपा को दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का व्यवहार कारपोरेट घरानों के प्रति क्या है और कृषि तथा किसानों के प्रति क्या है। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दो गुनी करने का वादा किया था वह कितना पूरा हुआ है वह हर किसान जानता है। किसानों बागवानी को लेकर पिछले पांच वर्षों में केन्द्र की घोषित योजनाओं का सच यह है कि कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एक लाख करोड़ से अधिक का धन लैप्स कर दिया गया है। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि और किसान के प्रति सरकार की कथनी और करनी में दिन रात का अन्तर है। आज आन्दोलनरत किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहा है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 201 सिफारिशें की थी जिनमें से 175 पर यूपीए के काल में ही अमल हो गया था। लेकिन 26 सिफारिशों पर ही अमल बाकी है। नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कृषि का समर्थन मूल्य तय करने के लिये सूत्र दिया था आज उसी पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। 1960 में न्यूनतम समर्थन मूल्य आवश्यक वस्तुओं के लिये लागू किया गया था। आज किसान इसी समर्थन मूल्य नियम को विस्तारित करके सारी कृषि उपज के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है। इस समर्थन मूल्य को वैधानिक कवच प्रदान करने की मांग है। यह व्यवहारिक सच है कि आज कृषि में हर चीज का लागत मूल्य कई गुना बढ़ चुका है और उसके अनुपात में किसान को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। ऐसे में यदि सरकार ने समय रहते किसानों की मांगों को नहीं माना तो इसके परिणाम गंभीर होंगे।

यूसीसी का विरोध विशुद्ध राजनीतिक, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं



गौतम चौधरी

धर्म, संप्रदाय, संस्कृति और धर्म के द्वारा बनाये हुये नियम इंसानी जिंदगी की खुशहाली के लिये बनाये गये हैं। अमूमन प्रत्येक धर्म अपने आदेशों में मानव कल्याण की ही शिक्षा देता है। इस्लामिक साहित्यों की यदि बात करें तो उसमें भी इंसानियत की भलाई के सैंकड़ों आदेश मौजूद हैं। यहां तक कि किसी दूसरे इंसान को पीड़ा न पहुंचे उसके लिए इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में व्यापक आदेश देखने को मिलते हैं। इस्लाम के जानकारों का तो यहां तक कहना है कि इतरा कर चलने से भी यहां मना किया गया है। यह परमपिता परमात्मा जिसे इस्लाम में अल्लाह की संज्ञा दी गयी है को पसंद नहीं है। जहां एक ओर इस्लामिक चिंतन में जमीन पर फसाद करने वालों की निंदा की गयी है, वहीं दूसरी तरफ किसी बेगुनाह का कत्ल करने वाले को सारी इंसानियत का कातिल कहा बताया गया है। इस्लामिक दुनिया के पवित्र ग्रंथों के सारे के सारे आदेशों के पीछे जनकल्याण की भावना निहित है और यही वजह है कि सारी जिंदगी अहले मक्का का जुल्म सहने के बाद, फतह मक्का के अवसर पर बदला लेने के सर्वसम्मत कानून के मौजूद होने के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने जुल्म करने वालों को आम माफी का ऐलान कर दिया था। यह ज्ञात दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी माफी थी।

भारत एक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहां के संविधान में सभी धर्मों और जातियों को समान

अधिकार और अवसर दिये जाने की बात कही गयी है। समान नागरिक संहिता जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) भी कहा जाता है, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा, उसे आने वाले समय में, लागू करने की बात की गयी थी। देश आजाद होने के 75 साल बाद अब शायद यही उपयुक्त समय है कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाये। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी रूप में धर्म के सिद्धांतों के विपरीत नहीं है। इस्लाम के कई व्याख्याकार, जिसमें सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी भी शामिल हैं, का मत है कि तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर पहले में इस्लामिक कई पारंपरिक नियम और कानून में परिवर्तन किये गये हैं। इसकी इस्लाम इजाजत भी देता है। यह इंसानियत के भलाई पर आधारित सिद्धांत की वकालत करता है। इस्लाम कहता है कि ऐसे मुल्क में जहां मुस्लिम नजरिया मजाहिब और फिक्र के लोग रहते हैं, उन सब पर एक कानून की हुकूमत होना चाहिए।

समान नागरिक संहिता नागरिकों को समान रूप से फौजदारी और दीवानी विधि के दायरे में लाना चाहती है। भारतीय दंड संहिता और दूसरी दंड विधियों के द्वारा दांडिक विधि समस्त भारत में, समान रूप से लागू है और बहुत से दीवानी मामलों में भी, समान नागरिक संहिता के ही तरह के नियम हैं। मसलन सरकारी नौकरी में, समान रूप से नियम लागू हैं।

भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों ने दावा किया है कि समान नागरिक संहिता के द्वारा धर्म के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध मात्र एक

राजनीतिक स्टंट के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। संविधान की दुहाई देने वाले प्रतिपक्षी नेता फिर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से ग्रस्त लोग संविधान सभा के उस निर्णय को क्यों नकारते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की रचना की जायेगी। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस शाहबानो केस के निर्णय के बाद देशव्यापी बवाल के बाद न सिर्फ तत्कालीन सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए कानून तक बना डाला, उसका लाभ क्या हुआ? जबकि 2010 में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक व्यवस्था देते हुये तलाकशुदा महिला को उसके विवाह होने तक अथवा आजीवन गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया गया है। ऐसे बहुत से व्यक्तिगत विधियों के उदाहरण हैं, जिनमें नागरिकों को समान कानूनों के अधीन ही रहना होता है।

कुछ लोगों के द्वारा समानता के अधिकार की प्रतीक समान नागरिक संहिता का विरोध किया जाना हास्यास्पद लगता है। जो लोग इसका विरोध धर्म और आस्था के नाम पर कर रहे हैं, उनके द्वारा कोरोना काल में सभी धर्मों के धार्मिक स्थल पर उपासना मर्यादित करने का इन कथित लोगों ने समर्थन किया था और तर्क दिया था कि पहले मानव जीवन को बचाना परम आवश्यक है और सभी को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। तो आज इन कथित लोगों द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों किया जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि यह मामला मात्र राजनीति है। यह एक दल विशेष को लेकर भ्रम फैलाना मात्र है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए ही है, न कि किसी विशेष धर्म के खिलाफ।

प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाले बजट का आकार 58 हजार 444 करोड़ रुपये

शिमला। सुकरू सरकार का दावा है कि 2024-25 का बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा दिखाने वाला बजट है। जहां आधुनिकतम तकनीक की सहायता से भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने वाली बात कही गई है वहीं प्रदेश के युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा शहरी क्षेत्र में अन्य विकल्पों के माध्यम से रोजगार के लिये प्रोत्साहन का वर्णन मिलता है। पर्यटन, मूलभूत संरचना, उद्योग क्षेत्रों में Artificial Intelligence तथा अन्य आधुनिकतम tools की सहायता से निजी निवेश से विकास को और अधिक गति देने की बात कही गई है। जैव ईंधन को चरणबद्ध ढंग से विद्युत से बदलने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुये हरित प्रदेश की कल्पना इस बजट में झलक पाती है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को और आगे बढ़ाते हुए इनसे संबंधित युवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस बजट में विस्तृत कार्य योजना का वर्णन है विकास प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के लिए महिलाओं विधवाओं दिव्यांगों तथा अन्य सभी वर्गों के लिये इस बजट के माध्यम से सुनहरे भविष्य की नींव रखी गई है। नशा तथा अवैध खनन जैसी विकृतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिये कई Initiatives लिये गये हैं। समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण को भी केंद्र में रखा गया है।

बजट के मुख्य बिन्दु

- ❖ 58 हजार 444 करोड़ रुपये का बजट आकार प्रस्तावित।
- ❖ 2023-24 के दौरान: -
 - प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत।
 - प्रतिव्यक्ति आय 2 लाख 35 हजार 199 रुपये अनुमानित।
 - राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 7 हजार 430 करोड़ रुपये अनुमानित।
- ❖ 'आत्मनिर्भर हिमाचल'
- ❖ समृद्ध किसान हिमाचल
- ❖ हरित और स्वच्छ हिमाचल
- ❖ बिजली राज्य हिमाचल
- ❖ पर्यटन राज्य हिमाचल
- ❖ कुशल और दक्ष हिमाचल
- ❖ स्वस्थ एवम् शिक्षित हिमाचल
- ❖ निवेशक मित्र हिमाचल
- ❖ नशा मुक्त हिमाचल
- ❖ अवैध खनन मुक्त हिमाचल
- ❖ समृद्ध और सम्पन्न हिमाचल

1. समृद्ध किसान हिमाचल

❖ किसानों को 'आत्मनिर्भर' बनाने की दिशा में प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत रोजगार के अवसर तथा आय में वृद्धि।

❖ बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक रूप से उगाये गये गेहूँ को 40 रुपये तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य।

❖ 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा।

❖ 'हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन' के अन्तर्गत 2 हजार 500 कृषि क्लस्टर समूहों को विकसित करके विभिन्न क्षेत्रों में high value फसलों को बढ़ावा।

❖ मोटे अनाज (Millets) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना।

❖ शिमला जिले में मेहंदली तथा शिलारू तथा कुल्लू जिला में बंदरोल में नई मंडियों का निर्माण।

❖ सिरमौर में पाँवटा साहिब, खैरी, घंडरी और नौहराधार, कुल्लू में चौराबिहाल, पतलीकुहल और खेगसू, मण्डी में टकोली और कांगनी, काँगड़ा

में जसूर, पासू तथा पालमपुर, तथा सोलन में परवाणू, कुनिहार और वाकनाघाट मंडियों का उन्नयन।

❖ किसानों की सुविधा के लिए Chat Bot और AI पर आधारित भू-अभिलेख, हेल्पडेस्क तथा किसानों के database सहित एक web आधारित कृषि पोर्टल और Mobile App बनाया जायेगा।

❖ सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों को उचित गुणवत्ता की पौध तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए एक 'Centre of Excellence Hi-Tech Vegetable Nursery Production' खोला जाएगा।

❖ पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्तमान 38 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 47 रुपये प्रति लीटर से 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ौतरी।

❖ 'हिम-गंगा' योजना के अन्तर्गत काँगड़ा के दगवार में 1.5LLPD (Lakh Litre Per Day) की क्षमता वाले 'Fully Automated Milk and Milk Products Plant' की स्थापना।

❖ ऊना तथा हमीरपुर में भी आधुनिकतम तकनीक से 'Milk Processing Plants' स्थापित किये जाएंगे।

❖ स्थानीय युवाओं को दूध ले जाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान पर 200 refrigerated milk vans उपलब्ध।

❖ सोलन जिले के दाइलाघाट में 'कृत्रिम गर्भाधन प्रशिक्षण केन्द्र' की स्थापना।

❖ प्रदेश में भेड़-बकरियों के लिए FMD Vaccination शुरू करने तथा उन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए 'भेड़-बकरी पालक प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ।

❖ 1 अप्रैल, 2024 से दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से APMC द्वारा ली जाने वाली फीस माफ।

❖ बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए एक 'State Level Task Force' का गठन किया जाएगा।

❖ निजी गौ-सदनों में आश्रित गौवंश के लिये दिये जाने वाले अनुदान 700 रुपये प्रति गौवंश प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,200 रुपये।

❖ एक 'बागवानी उत्कृष्टता केन्द्र' की स्थापना। जो गुणवत्ता, कौशल, पर्यटन तथा बाज़ार सम्बन्धित आवश्यकताओं हेतु 'One Stop Resource Centre' के रूप में कार्य करेगा।

❖ राज्य के Sub-tropical क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक 'Fruit Processing Unit' स्थापित किये जाएंगे।

❖ अमरूद, नीम्बू तथा अन्य Sub-tropical फलों को बढ़ावा देने के लिये mother trees/ bud wood banks के लिए 'Foundation Block' की स्थापना की जाएगी।

❖ 2024 के सेब सीज़न से universal carton का प्रयोग आरम्भ कर दिया जाएगा।

❖ 20 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण के लिए मछुआरों को 80 प्रतिशत उपदान पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

❖ जिला हमीरपुर में 'Centre of Excellence' के रूप में एक नए 'Carp Fish Farm' की स्थापना।

❖ मछुआरों को मोटरसाइकिल, श्री-व्हीलर तथा ice-boxes उपदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

❖ 10-10 नए 'Biofloc Fish Production' तालाबों तथा इकाईयों की स्थापना की जाएगी।

❖ तीन नई 'Feed Mills' की स्थापना की जाएगी।

❖ 150 नई टाउट मछली उत्पादन इकाईयों सहित नई trout hatcheries की स्थापना की जाएगी।

2. हरित, स्वच्छ तथा बिजली राज्य हिमाचल

❖ पेखुबेला स्थित 32 मैगावाट क्षमता वाले हिमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट को मार्च, 2024 तक के अंत तक commission किया जाएगा।

❖ ऊना में अघलोर स्थित 10 मैगावाट क्षमता वाला 'सोलर पावर प्लांट' जून, 2024 तक बनकर तैयार।

❖ ऊना के भांजल में 5 मैगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का सितम्बर, 2024 तक लोकार्पण।

❖ 'राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना' के अन्तर्गत निजी भूमि पर 45 प्रतिशत उपदान पर 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्य में गति।

❖ बाल एवम् बालिका आश्रमों तथा वृद्ध आश्रमों और Rajiv Gandhi Day Boarding Schools में ग्रिड से जुड़े Roof Top Solar Plant और Water Heating System स्थापित।

❖ Re-vamped Distribution Sector Scheme के माध्यम से Aggregate Technical and Commercial (AT&C) Losses को कम करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना का कार्यान्वयन।

❖ बिजली उत्पादन के साथ-साथ एक Efficient Transmission and Distribution Network के लिए चार transmission lines तथा 6 EHV sub-station पूरे किये जाएंगे।

❖ 327 अतिरिक्त डीज़ल buses को electric buses से बदला जाएगा।

❖ 'Rajiv Gandhi Swarozgar Start-up Yojana' के अन्तर्गत 40 प्रतिशत उपदान पर e-taxis चलाने के लिए 10,000 permit दिये जाएंगे।

❖ वन विभाग, HRTC, HPTDC के सभी तथा GAD के पात्र वाहन e-vehicle से बदल दिये जाएंगे।

❖ 'वाहन स्कैप नीति' के अन्तर्गत प्रदेश में 'Vehicle Scrapping Facility Centres (VSFCs)' की स्थापना।

❖ 'हरित हिमाचल' की दिशा में 'Green Himachal', biodiversity parks, nature parks, river side parks स्थापित किए जाएंगे।

❖ ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तथा उसे green बनाने के लिए 'मुख्य मन्त्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना' आरम्भ।

❖ कृषि और बागवानी क्षेत्र पर बदलती जलवायु के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में एक 'Need Assessment Study (NAS)' शुरू।

❖ Forest Clearance cases के शीघ्र निपटान के लिए जिला स्तरीय समीतियों का गठन।

3. पर्यटन राज्य हिमाचल

❖ काँगड़ा के गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए Rehabilitation and Resettlement (R&R) Plan को शीघ्र ही अंतिम रूप देकर भू-अधिग्रहण का कार्य आरम्भ

कर दिया जायेगा।

❖ पर्यटकों को प्रदेश में प्रवास के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित सभी Home Stay Units को 'Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act' के अधीन लाया जाएगा।

❖ 16 प्रस्तावित Heliports में से प्रथम चरण में 9 Heliports क्रमशः हमीरपुर में जसकोट, काँगड़ा में रक्कड़ और पालमपुर, चम्बा में सुल्तानपुर, कुल्लू में आलू ग्राउंड, मनाली, किन्नौर में शारबो, तथा लाहौल-स्पिति में जिस्पा, सिस्सू और रांगरिक में।

❖ कुफरी के नजदीक हासन घाटी के मशहूर पर्यटक स्थल पर एक sky walk bridge.

❖ Nature Park, मोहाल तथा बिजली महादेव के बीच Hybrid Annuity Model (HAM) पर एक 3.2 किलोमीटर लम्बे रोपवे का निर्माण कार्य आरम्भ।

❖ स्वदेश दर्शन-2 के अन्तर्गत पौंग डैम के विकास और प्रबन्धन के लिए एक master plan तैयार किया जाएगा।

❖ लाहौल-स्पिति में चंद्रताल, काज़ा और तांदी तथा किन्नौर में रकछम और नाको-चांगो-खाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

❖ पर्यटकों की सुविधा के लिए कालका से परवाणु तक की broad gauge rail line तथा जेजों से पोलियों तक की रेललाइन बिछाने के लिए भी भारत सरकार से अनुरोध।

4. स्वस्थ, शिक्षित, कुशल एवम् दक्ष, हिमाचल

❖ 'Dr. Radhakrishnan Medical College, Hamirpur' में आधुनिकतम diagnostic तथा treatment facilities के साथ 'State Cancer Institute' की स्थापना।

❖ कैंसर पीड़ित मरीजों को chemotherapy तथा Palliative Care की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों तथा चयनित 'आदर्श स्वास्थ्य केन्द्रों' पर 'Cancer Day Care Centres' की स्थापना।

❖ Indira Gandhi Medical College, Shimla में कैंसर पीड़ित रोगियों के Advanced Radio Therapy तकनीक से उपचार के लिए LINAC (Linear Accelerator Machine) स्थापित।

❖ 'PGI Satellite Centre, Una' में चल रहे सभी कार्यों को गति।

❖ 53 स्वास्थ्य संस्थानों में 'Hospital Management Information Service (HMIS)' की स्थापना।

❖ Scrub Typhus के बढ़ते हुए मामलों के दृष्टिगत में 'State Level Scrub Typhus Research Unit' स्थापित।

❖ Dr. Rajinder Prasad Government Medical College, Tanda और Kamla Nehru Hospital, Shimla में नवजात शिशुओं में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए उनके तथा जच्चाओं के लिए 'Lactation Management Centres' स्थापित।

❖ प्रत्येक जिले में सभी टैस्ट सुविधाओं सहित एक 'Integrated Public Health Lab' की स्थापना।

❖ Dr. Rajindra Prasad Medical College, Tanda में General Nursing and Midwifery (GNM) स्कूल को नहसग कॉलेज में स्तरोन्नत।

❖ बड़ी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, पाँवटा और ऊना औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी कामगारों की health screening के लिए एक 'Guest Worker Screening Project' आरम्भ।

❖ 'हिमकेयर' तथा 'सहारा' योजनाओं के कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर के domain experts की सहायता से आवश्यक सुधार।

❖ प्राथमिक, प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उचित गुणवत्ता और प्रेम के class-rooms, smart class-rooms with smart boards, audio-visual teaching aids, leaning software, proper seating arrangements; full strength of teachers, playground, clean toilet के साथ-साथ सभी सुविधाएं।

❖ 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अनुरूप प्रदेश में स्कूली स्तर पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की जायेगी जिसमें तीन साल का pre-school 'बाल वाटिका' पाठ्यक्रम भी शामिल।

❖ शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 'Institutions of Excellence' के रूप में विकसित किया जाएगा।

❖ स्कूलों और समाज के बीच बेहतर ताल-मेल के लिए तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 'अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान' योजना प्रारम्भ।

❖ प्रत्येक उप-मण्डल में उप-मण्डलाधिकारियों को सभी primary schools का महीने में एक दिन बारी-बारी से अनिवार्य रूप से review meeting.

❖ सभी शिक्षण संस्थाओं की वार्षिक Ranking और उनके लिए Performance Based Grant की व्यवस्था की शुरुआत।

❖ पढ़ने-पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश में 'पढ़ो हिमाचल' के नाम से एक व्यापक जन अभियान प्रारम्भ।

❖ शिक्षा स्तर में सुधार लाने में प्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण को और अधिक result oriented बनाने के लिए District Institute of Education Training (DIETs) तथा State Council of Educational Research (SCERT) के नियमों में बदलाव लाकर State Institute of Educational Management and Training (SIEMAT) का पुनर्गठन।

❖ सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक सुरक्षित एवम् स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध करवाई जायेगी।

❖ पाँचवी कक्षा से हिमाचल के इतिहास एवम् संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, basic hygiene तथा अन्य सामान्य ज्ञान के विषयों पर अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम आरम्भ।

❖ प्रत्येक जिला मुख्यालय, उपमण्डल तथा पंचायत मुख्यालय पर एक आधुनिकतम सुविधाओं सहित पुस्तकालय।

❖ पाँच राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों क्रमशः लाहड़ और नगरोटा बगवां (काँगड़ा), अमलेहड़ और भोरंज (हमीरपुर), तथा संगनाई (ऊना) का निर्माण कार्य आरम्भ।

❖ जिला हमीरपुर में श्रम विभाग की EEMI पोर्टल पर निजी क्षेत्र के शेष पृष्ठ 6 पर.....

प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाले बजट का आकार 58 हजार 444 करोड़ रुपये.....पृष्ठ 5 का शेष

और employer को जोड़ा जायेगा तथा 2024-25 में 180 campus interviews आयोजित किये जायेगे।

5. निवेशक मित्र हिमाचल

किन्नौर, चम्बा और लाहौल व स्पिति में 4 Antifreeze पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य। शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्य स्तर पर शहरी विकास निदेशालय में एक पर्यावरण cell की स्थापना।

ज्वाली, हमीरपुर, बैजनाथ-पपरोला तथा नेरचौक में 135 Litres Per Capita Per Day (LPCD) की क्षमता वाली पेयजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जायेगा।

नाहन, अर्की निरमंड, पालमपुर तथा जोगिन्द्रनगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य शीघ्र आरम्भ।

500 किलोमीटर लम्बी सड़कों की upgradation, 325 किलोमीटर नई सड़कों तथा 8 पुलों का निर्माण।

15 बस्तियों को सड़क से जोड़ा जायेगा।

NABARD के माध्यम से RIDF के अन्तर्गत 205 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों, 305 किलोमीटर सड़कों पर cross drainage, 425 किलोमीटर लम्बी tarred सड़कों तथा 27 पुलों का निर्माण किया जाएगा।

CRIF के अन्तर्गत 5 स्वीकृत सड़कों, जिया-मनीकरण सड़क, शाहपुर-सिंहता-चुवाड़ी मार्ग तथा बागछाल-मैहरे-बड़सर का उन्नयन, यास नदी पर टैरेस तथा स्थाना को जोड़ने वाले पुल तथा पडोगा तियूड़ी में स्वां नदी पर पुल का निर्माण।

अधिक ऊँचाई वाली सड़कों पर calcium chloride तथा Brine Solution का प्रयोग किया जायेगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ न जम सके और सम्भावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

एक नई “औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति, 2024” आरम्भ।

युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई “स्टार्ट-अप नीति, 2024” आरम्भ।

बढ़ी हुई Electricity Duty (ED) उन उपभोक्ताओं द्वारा देय नहीं होगी, जिन्हें ‘हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति, 2019’ के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य अवधि की समाप्ति तक ED का भुगतान करने में छूट दी गई थी।

शीतलपुर से जगातखाना तक सड़क बनाई जायेगी जो ‘Medical Device Park’ डेरोवाल को बढ़ी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगी।

हिमाचल प्रदेश को Films की shooting के लिए हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी, 2024 का कार्यान्वयन।

सूचना एवम् जन सम्पर्क विभाग में ‘Film Facilitation Cell’ की स्थापना की जायेगी।

फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा अनुमति प्रदान करने के लिए web portal की स्थापना।

पाँच शहरी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिये National Housing Bank के माध्यम से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के अन्तर्गत इन

शहरी क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति।

6. नशा मुक्त हिमाचल

राज्य स्तर पर सभी सुविधाओं सहित कण्डाघाट में एक “आदर्श नशा निवारण केन्द्र” की स्थापना।

उपमण्डल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक ‘effective monitoring and reporting system’ की स्थापना।

हमीरपुर तथा ऊना के पंजोआ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

मनाली बंदरोल में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण।

रैहन और देहरा में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

खरीड़ी, नादौन में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।

कसुम्पटी में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।

जयसिंहपुर में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।

ढली बाईपास में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।

ओलम्पिक्स खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि 5 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिये 3 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिये 2 करोड़ रुपये।

एशियन खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि 4 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिये 2 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिये 1 करोड़ रुपये किया जायेगा।

कॉमन वेल्थ खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिये 2 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिये 1 करोड़ रुपये किया जायेगा।

टीम स्पर्धाओं में विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को प्राप्त पदक के आधार पर उपरोक्त पुरस्कार राशि में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व के अनुपात में बराबर राशि।

राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को AC 3 Tier किराया तथा 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिये economy class air fare।

सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3 प्रतिशत खेल कोटा के अन्तर्गत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जायेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 250 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।

अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।

सभी खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर होने वाली खेलों में भाग लेने पर समान रूप से 500 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।

प्रदेश के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपये तथा 400 रुपये की डाइट मनी दी जायेगी।

7. अवैध खनन मुक्त हिमाचल

सभी परिवहन Barrier पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR)/Close

Circuit Television (CCTV) Cameras की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी जिससे कर चोरी को समाप्त किया जा सके और सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो सके।

करदाताओं की सुविधा के लिये VAT तथा अन्य करों के भुगतान के लिए ‘mobile app’ की शुरुआत।

प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक एवम् व्यापार केन्द्रों पर विभिन्न करदाताओं से feedback लेने तथा उन्हें पेश आ रही समस्याओं की जानकारी लेने के उद्देश्य से ‘करदाता संवाद अभियान’ आरम्भ किया जायेगा।

अवैध तथा unscientific mining को रोकने के उद्देश्य से एक GIS Based App आरम्भ।

8. समृद्ध और सम्पन्न हिमाचल

वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी तथा transgender पेंशन के 40 हजार नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित।

दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिये कण्डाघाट में एक “Centre of Excellence for Education of Divyangjans” की स्थापना। इसमें आवासीय सुविधाओं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाओं सहित पात्र दिव्यांग बच्चों के लिये रहने के लिए किराये के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी।

0-27 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाएं।

“Institute for Children with Special Disabilities (ICSA, Dhalli)” को “Centre of Excellence for Education of Divyangjans” में स्थानान्तरित।

नई योजना “मुख्य मंत्री सुख आरोग्य योजना” आरम्भ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ऐसे वृद्धों, जोकि आयकर न दे रहे हों, को मुफ्त चिकित्सा सुविधा।

एक नई योजना “मुख्य मंत्री सुख-शिक्षा योजना” आरम्भ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों की शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी।

विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता-पिता के सभी पात्र बच्चों के RD खाते में 18 वर्ष की आयु तक 1 हजार रुपये प्रतिमाह दिये जायेगे।

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये बाजार मांग के अनुरूप GST, Tally, Artificial Intelligence, Data Management, Machine Learning, Cyber Security, Auto-CAD इत्यादि नए Courses।

वाल्मीकि समाज के भाईयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता के लिये नई योजना “महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना” आरम्भ।

मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये की बढ़ौतरी। विधवा, एकल/बेसहारा/दिव्यांग महिला मनरेगा कामगारों को मकान बनाने के लिये 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जायेगी।

नगर निगम धर्मशाला, सोलन और शिमला और नगर परिषद नालागढ़ और परवाणू में Economically Weaker Sections (EWS)/slumdwellers से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों को 363 मकान आवंटित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है।

Artificial Intelligence

(AI) के साथ-साथ data analytics की सहायता से evidence based नीति निर्धारण के लिए work plan की शुरुआत की जाएगी।

निवेशकों द्वारा किये गये 5G connectivity के लिए ऑनलाइन आवेदनों के शीघ्र निपटारे हेतु Right of Way (RoW) Portal को आवयक संशोधनों सहित अपडेट।

State Data Centre (SDC) की upgradation का कार्य अगस्त, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

हिम परिवार रजिस्ट्री के सफल कार्यान्वयन के बाद विभिन्न नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकीकृत किया जाएगा।

ऑनलाइन चालान के लिए विभागीय अधिकारियों को e-Challan and e-POS Machines उपलब्ध करवाई जाएगी।

9. कर्मचारी, पैरा वर्कर, मनरेगा कामगार, तथा अन्य वर्गों का कल्याण

कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन तथा पेंशन से सम्बन्धित एरियर्स का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू।

1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के leave encashment and gratuity से सम्बन्धित एरियर्स का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू।

1 अप्रैल, 2024 से 4 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते की किश्त जारी।

1 अप्रैल, 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LTC की सुविधा। दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगे।

पंचायत वैटनरी असिस्टेंट को मिलने वाले 7 हजार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7 हजार 500 किया जाएगा।

बढ़े हुए मानदेय के साथ ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,000 रुपये मासिक, मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपये, ऑगनवाड़ी सहायिका को 5,500 रुपये, आशा वर्कर को 5,500 रुपये, मिड डे मील वर्कर को 4,500 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 5,000 रुपये, जल रक्षक को 5,300 रुपये, जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 5,000 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प-ऑपरेटर को 6,300 रुपये, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये, पंचायत चौकीदार को 8,000 रुपये, राजस्व चौकीदार को 5,800 रुपये, राजस्व लम्बरदार को 4,200 रुपये प्रतिमाह मिलेगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये, SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,900 रुपये, IT Teachers को 1,900 रुपये, SPOs को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी दी जाएगी।

पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के अध्यक्षों के मानदेय में 4,000 रुपये, उपाध्यक्षों के 3,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद के 1,300 रुपये, अध्यक्ष, पंचायत समिति के

1,900 रुपये, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 1,400 रुपये, सदस्य, पंचायत समिति के मानदेय में 1,200 रुपये, प्रधान के मानदेय में 1,200 रुपये व उप प्रधान ग्राम पंचायत के मानदेय में 800 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि।

स्थानीय नगर निकायों में महापौर के मानदेय में 4,000 रुपये, उप-महापौर नगर निगम के मानदेय में 3,000 रुपये, काऊंसलर नगर निगम के मानदेय में 1,400 रुपये, अध्यक्ष नगर परिषद के मानदेय में 1,700 रुपये, उपाध्यक्ष नगर परिषद के मानदेय में 1,400 रुपये, पार्षद नगर परिषद के मानदेय में 700 रुपये तथा प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,400 रुपये, उप-प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,100 रुपये एवम् सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 700 रुपये की वृद्धि।

सभी 2 हजार 61 Forest Beats में एक-एक वन मित्र की नियुक्ति।

वन विभाग में Forests Guards के 100 रिक्त पदों की भर्ती।

पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़कर 1,000 रुपये की गई।

10. अन्य

सभी वाहनों की Fitness, Automated Testing Centres के माध्यम से अनिवार्य।

बगलामुखी रोपवे का निर्माण कार्य पूरा करके इसी वर्ष में इसे प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

खैर की silviculture felling से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि। 10 Forest Divisions में लगभग 13 हजार खैर के पेड़ काटने की योजना। इससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

माननीय न्यायालय से चील के पेड़ काटने की अनुमति के लिए भी याचिका दायर करेगी। इससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ Eco-System Services की गुणवत्ता भी सुधरेगी।

भू-अभिलेखों का अनुवाद संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध विभिन्न भाषाओं में करवाने का कार्य शीघ्र शुरू।

शहरी क्षेत्रों में स्थित police stations के प्रांगण अथवा station के आस-पास उनमें कार्यरत police staff के लिए आवासीय सुविधाएं।

काँगड़ा के चंगर बड़ोह में sub fire station, मण्डी के कोटली और लडभडोल में fire post खोलने तथा ठियोग स्थित fire post को sub fire station में उन्नयन।

निरमंड, कुनिहार और उबादेश (कोटखाई), छोटा भंगाल तथा काँगड़ा के चुहार घाटी में अग्निशमन इकाईयाँ खुलेगी।

विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये किया जाएगा।

‘विधायक ऐच्छिक निधि’ को 13 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र कर दिया जाएगा।

‘विधायक क्षेत्र विकास निधि’ के अन्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र राशि 2 करोड़ 20 लाख रुपये।

2024-25 में 1 हजार करोड़ रुपये उन कार्यों पर खर्च किए जाएंगे जो पूरा होने के करीब हैं।

हिमाचल में इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी भाजपा: जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। जयराम ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के नायक नरेन्द्र मोदी की गारंटी है, जो उनके द्वारा दी गई बाकी गारंटियों की तरह निर्धारित समय में पूरी होगी। इस संकल्प को हर भारतीय का सहयोग मिल रहा है। बहुत ही जल्दी भारत

को आयुष्मान भारत के इलाज के दायरे में लाना भी कोई आसान काम नहीं था लेकिन यह सारे लक्ष्य प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में निर्धारित समय में हासिल होंगे। जो काम सत्तर साल में नहीं हुआ, उससे ज्यादा काम दस साल के दौरान हुआ। दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, चाहे वैश्विक

भावना है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने को लेकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब धारा 370 समाप्त होने के बाद देश भी बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें देकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। बीजेपी हर बूथ पर 370 वोटों से ज्यादा की बढ़त हासिल करेगी।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की अलोकप्रियता का ग्राफ आसमान पर पहुंच गया है। झूठी गारंटियों और वादों के बाद की रही कसर सरकार के दूसरे बजट ने निकाल दी। सरकार का यह बजट उनकी बाकी बातों की तरह सिर्फ जुबानी जमाखर्च निकला। विकास के लिए खर्च किये जाए वाले पूंजीगत व्यय में कटौती की गई। गरीबों के लिए कोई योजना नहीं लायी गयी। गारंटियों के मामले में इस बार भी खामोशी धारण की गई। प्रदेश का हर वर्ग आज परेशान है। सड़कों पर है। प्रदर्शन कर रहा है। न सरकार नौकरी दे रही है और न रोजगार स्थापित करने में किसी प्रकार की सहायता कर रही है। ऐसे में इस बार प्रदेश की जनता कांग्रेस को हर बूथ हराकर बीजेपी को चार की चारों सीटों पर विजय श्री दिला रही है।

शिमला/शैल। मिस अर्थ इंडिया-2022 वंशिका परमार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू

नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने वंशिका से महिला सशक्तिकरण में प्रदेश सरकार के प्रयासों को संबल प्रदान करने तथा



से भेंट की।

हमीरपुर जिला के नादौन उपमण्डल के धनेटा गांव से सम्बंध रखने वाली वंशिका ने 19 वर्ष की आयु में नवम्बर, 2022 में फिलीपीन्स में आयोजित प्रतियोगिता में यह खिताब हासिल किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वंशिका की इस उपलब्धि से अन्य लड़कियों को भी अपनी पसंद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्रदेश की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों से हिमाचल का

एकल बेटियों के कल्याण के लिए सहयोग करने का आग्रह किया।

वंशिका परमार ने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में अपना सहयोग प्रदान करने की भी इच्छा जताई। उन्होंने अवगत करवाया कि वह वर्ष-2023 में घाना की पर्यटन दूत रह चुकी हैं और फिलीपीन्स में भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के अभियान से जुड़ी रही हैं।

इस अवसर पर वंशिका परमार की माता रितु परमार तथा पिता ग्रुप कैप्टन सुशील कुमार परमार भी उपस्थित थे।

मंडी शिवरात्रि में आने वाले देवी-देवताओं की सुविधाओं में किया जाएगा इजाफा

शिमला/शैल। मंडी शिवरात्रि मेले में आने वाले देवी-देवताओं और उनके साथ आने वाले देवतुओं की सुविधाओं बारे आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित बनाने के लिए एडीएम डॉ. मदन कुमार की अध्यक्षता सर्व देवता कमेटी के सदस्यों और मेला आयोजन से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी के साथ बैठक आयोजित हुई। एडीएम ने कहा कि मंडी का शिवरात्रि मेला देवताओं को समर्पित मेला है। मेले में आने वाले देवताओं और देवतुओं को दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्हें इस बार पहले से दी जाने वाली सुविधाओं में और इजाफा किया जाएगा।

मदन कुमार ने बताया कि मेले में स्थापित परंपराओं का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित होगा। सभी देवताओं को मेले में पधारने के लिए विधिवत निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते

हुए कहा कि सभी के सहयोग से मेला बड़ी धूमधाम से आयोजित होगा।

उन्होंने सर्व देवता कमेटी के सदस्यों से कहा कि मेले के दौरान अगर किसी भी प्रकार समस्या आती है तो इसे अधिकारियों के ध्यान में लाएं। उसका समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को देवताओं और देवतुओं के ठहरने की व्यवस्थाओं को समय पर चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिये। नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि मेले के दौरान जहां पर भी देवता और देवतु ठहरते हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्म तैनात करें।

सर्व देवता कमेटी के आग्रह पर एडीएम ने कहा कि शिवरात्रि मेले के दौरान निकलने वाली जलेब में वरीयता क्रम का पूरी तरह पालन होगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की तैनाती होगी।

नवउदारवादी नीतियों को बढ़ावा देने वाला बजट: डॉ. ओंकार शाद

शिमला/शैल। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी के सचिव डॉ. ओंकार शाद ने सुक्खू सरकार के बजट को नवउदारवादी नीतियों को बढ़ावा देने वाला बजट करार दिया है। यह बजट मिला जुला है। पार्टी ने गाय व भैंस के दूध से समर्थन मूल्य को 45 व 55 रुपये घोषित करने के कदम का स्वागत किया है। पार्टी का मानना है कि बजट में आय के संसाधन जुटाने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। आय व राजस्व संसाधनों के अभाव में बजट में की गई घोषणाओं को पूरा

करना बेहद मुश्किल कार्य होगा। बजट में रोजगार के संदर्भ में कोई पुक्ता ब्लू प्रिंट नहीं है। बजट में शिक्षा क्षेत्र की अनदेखी है व नई शिक्षा नीति को लागू करने के कारण शिक्षा आम छात्रों से दूर होगी। बजट में कृषि संकट से निपटने व किसानों को सुदृढ़ करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बजट में केवल लीपापोती है। निगमों बोर्डों के कर्मचारियों की ओपीएस बहाली पर बजट खामोश है। महिलाओं, पिछड़े व वंचितों की आस भी बजट में पूर्ण नहीं हुई है।



विकसित देशों के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य बड़ा है, कठिन है लेकिन प्रधानमंत्री के लिए वह लक्ष्य ही क्या जो दुष्कर और असाध्य न हो। देश में डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ लोगों के खाते में बिना एक पैसे के भ्रष्टाचार के भेजना भी कठिन कार्य था। दस करोड़ शौचालय, चार करोड़ आवास, 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 60 करोड़ लोगों

स्तर पर हुई बड़ी घटनाओं में भारत लोगों का वापस लाने का लक्ष्य हो या कतर में फांसी की सज़ा पाये भारतीयों की रिहाई। पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री की ताकत देखी है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार चार सौ पार के आंकड़े के साथ नरेन्द्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हमारे लिए 370 केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक

पुलिस विभाग में भरे जाएंगे कांस्टेबल के 1226 पद महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पुलिस विभाग में पुरुष एवं महिला कांस्टेबल के 1226 पद भरने की अनुमति प्रदान की गई है। इनमें 818 पद पुरुष कांस्टेबल 351 महिला कांस्टेबल तथा 57 पद पुरुष चालक के शामिल हैं।

तृतीय श्रेणी के यह सभी पद सीधी भर्ती के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे और इनमें महिला उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। विभाग की ओर से भर्ती संबंधी संस्तुति आयोग को भेज दी गई है।

इन पदों के लिये लिखित परीक्षा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया

है। यह सभी 1226 पद संबंधित जिला के जनसंख्या अनुपात और आरक्षण रॉस्टर के अनुसार भरे जाएंगे।

बिलासपुर जिला से 46 पद पुरुष कांस्टेबल तथा 19 पद महिला कांस्टेबल व तीन पद चालक के भरे जाएंगे। इसी प्रकार चंबा जिला से 62 पद पुरुष व 27 पद महिला कांस्टेबल के तथा चार पद चालक के हमीरपुर जिला से 54 पद पुरुष व 23 पद महिला कांस्टेबल तथा चार पद चालक के भरे जाएंगे। कांगड़ा जिला से 180 पद पुरुष व 77 पद महिला कांस्टेबल तथा 12 पद चालक के, किन्नौर जिला से 10 पद पुरुष और चार पद महिला कांस्टेबल के व एक पद चालक का कुल्लू जिला से 52 पद पुरुष व 22 पद

महिला कांस्टेबल तथा चार पद चालक के लाहौल स्पीति जिला से चार पद पुरुष व दो पद महिला कांस्टेबल के मंडी जिला से 119 पद पुरुष व 51 पद महिला कांस्टेबल तथा आठ पद चालकों के भरे जाएंगे।

शिमला जिला के 97 पद पुरुष कांस्टेबल व 42 पद महिला कांस्टेबल तथा सात पद चालक के भरे जाएंगे। सिरमौर जिला से 63 पद पुरुष व 27 पद महिला कांस्टेबल व पांच पद चालकों के सोलन जिला से 69 पद पुरुष व 30 पद महिला कांस्टेबल के तथा पांच पद चालक के ऊना जिला से 62 पद पुरुष व 27 पद महिला कांस्टेबल के तथा चार पद चालकों के भरे जाएंगे।

फसलों को हुए नुकसान का करें आकलन: हेम राज बैरवा

शिमला/शैल। उपायुक्त हेम राज बैरवा ने कहा कि कांगड़ा जिला में कम बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने तथा फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों को नियमों के तहत मुआवजा दिलाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। धर्मशाला में डीसी आफिस के सभागार में सूखे से निपटने की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि इस बार जनवरी तथा फरवरी माह में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है तथा ऐसी स्थिति में किसी स्तर पर पेयजल संकट से लोगों को नहीं गुजरना पड़े इस के लिए जल शक्ति विभाग को तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए तथा पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के लिए भी आवश्यक प्लान तैयार रखना चाहिए ताकि किसी भी स्तर

पर लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि सिंचाई के लिए तैयार कूहलों का रखरखाव भी सही तरीके हो इस के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि भविष्य में वर्षा जल संग्रहण ढांचों को विकसित करने के लिए विशेष बल दिया जाएगा ताकि सूखे इत्यादि की स्थिति से निपटा जा सके। इस बाबत जल शक्ति, कृषि तथा बागबानी विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य योजना तैयार करें ताकि सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो सके।

उपायुक्त हेम राज बैरवा ने स्वास्थ्य विभाग को भी दवाइयों का उपयुक्त स्टॉक रखने तथा खाद्य आपूर्ति विभाग को भी खाद्य सामग्री के भंडारण के लिए

उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी स्तर पर लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि बारिश कम होने के कारण जंगलों में आग की आशंका भी बनी रहती है तथा दमकल विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहते हुए कार्य करना चाहिए। उन्होंने दमकल विभाग को फायर हाईड्रेंट्स चेक करने तथा तकनीकी खराबी के बारे में जल शक्ति विभाग को सूचित करने के निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले एडीएम डा हरीश गजजू ने सूखे से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर एडीसी सौरभ जस्सल तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे तथा सभी उपमंडलों के एसडीएम वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे।

कांग्रेस के उम्मीदवार वॉटरसैस का विरोध करने वाली कंपनियों के वकील है विपक्ष ने उछाला मुद्दा

शिमला/शैल। राज्यसभा की सीट के लिये होने वाले चुनाव कहीं सरकार के लिये अनिष्टकारक न सिद्ध हो जाये इसकी आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है वह संयोगवश इसी सरकार के सबसे बड़े फौसले वॉटरसैस को चुनौती देने वाली बिजली उत्पादक कंपनियों का वकील है। सरकार ने अपने संसाधन बढ़ाने के लिये बिजली उत्पादक कंपनियों पर वॉटरसैस



लगाया है। इसके लिये सरकार ने वाकायदा विधानसभा में एक एक्ट पारित कर इसको अंजाम दिया है। इसके लिये वॉटरसैस आयोग तक का गठन कर दिया गया है। लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी के प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार होने से सुक्खू सरकार और कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद हो गयी है। विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत है और इस नाते उसकी जीत हो सकती है। लेकिन अब आने वाले लोकसभा चुनावों के बड़े मंच पर यह सवाल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछा जायेगा की वह वॉटरसैस लगाने को कैसे जायज ठहराते हैं जब तुम्हारा ही राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता देश का एक बड़ा वकील अदालत में तुम्हारे फौसले के विरोध में खड़ा है तो ऐसा एक्ट जनहित कैसे हो सकता है? क्या सरकार तब इस एक्ट को वापस लेगी? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मनु सिंघवी के नामांकन दायर करने के बाद इसको लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है।

यदि इस उम्मीदवारी के राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाये तो पहला सवाल उठता है कि जब सिंघवी का नाम राज्यसभा के लिये हिमाचल से आया तब

➤ कांग्रेस के असंतुष्टों को सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने का मिला मुद्दा

➤ आसान नहीं होगी कांग्रेस की जीत

क्या इस वॉटरसैस वाली पृष्ठभूमि को संज्ञान में नहीं लिया गया?

संभव है कि इस पृष्ठभूमि की जानकारी हाईकमान को न रही हो लेकिन मुख्यमंत्री को तो यह जानकारी अवश्य रही होगी। ऐसे में दूसरा सवाल उठता है कि यह जानकारी होने के बावजूद सिंघवी की उम्मीदवारी को इसलिये स्वीकार कर लिया गया कि प्रदेश की जनता को अब पूछने बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इन नैतिक सवालों के आने में सरकार ने जितनी भी सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाये हैं उनके औचित्य पर

स्वतः सवाल उठते जायेंगे। ऐसे में यह फैसला एक ऐसा आत्मघाती कदम हो गया है जो कांग्रेस और सरकार का कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा।

दूसरी और इस समय सुक्खू सरकार और संगठन में तालमेल का बड़ा अभाव चल रहा है। कार्यकर्ताओं को सरकार में उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायतें हाईकमान तक भी पहुंची हुयी हैं। राजेन्द्र राणा और सुधीर शर्मा तो विधायक दल की बैठक से भी गायब रहे हैं। पूर्व मंत्री और जिला मंडी के कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने तो पार्टी से ही त्यागपत्र दे दिया है। इससे पहले अभिषेक राणा ने अपने पद

से त्यागपत्र दे दिया है। पार्टी में मुख्यमंत्री के व्यवहार को लेकर एक बड़े स्तर पर रोष फैलता जा रहा है। लोकसभा चुनावों में पार्टी को करारी हार मिलने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है की पार्टी के असंतुष्ट विधायक अपना रोष प्रकट करने के लिये इस चुनाव को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भाजपा ने अपने पच्चीस विधायकों के बल पर ही अपना उम्मीदवार उतार दिया हो ऐसा नहीं लगता। क्योंकि राष्ट्रीय परिदृश्य में कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करना मोदी-भाजपा

की आवश्यकता बनता जा रहा है। हिमाचल में तो सरकार अपने ही बोझ से इतनी दब चुकी है की चाहकर भी इस स्थिति से बाहर नहीं आ सकती। मुख्य संसदीय सचिवों के मामले में मार्च में फैसला आने की संभावना है और तब पार्टी के समीकरणों में भारी बदलाव आयेगा यह तय है। इसलिये भाजपा ने हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया है। जो कल तक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष था। वह



कांग्रेस को अच्छी तरह समझता है। मुख्यमंत्री के साथ हर्ष महाजन के रिश्ते जगजाहिर हैं। ऐसे में यह चुनाव एक बड़े घटना चक्र का पहला पड़ाव माना जा रहा है।

एसएमसी अध्यापकों ने 1900 रुपए मानदेय बढ़ाने का किया विरोध

शिमला/शैल। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया इसमें एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1900 रुपए की मासिक बढ़ौतरी की गई है इस पर एसएमसी शिक्षकों का कहना है कि वे नियमितीकरण की मांग को लेकर 27 जनवरी से निरन्तर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और 8 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं।

अध्यापकों का कहना है कि 28 जून 2023 को सरकार द्वारा एसएमसी अध्यापकों की नियमितीकरण के लिये एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की इसने अपनी

रिपोर्ट 31 दिसम्बर 2023 तक कैबिनेट को सौंपी थी लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद 27 जनवरी 2024 को एसएमसी अध्यापक क्रमिक अनशन पर बैठ गये। पिछले 12 वर्षों से लगातार सेवायें दे रहे एसएमसी अध्यापकों का सरकार पर भेदभाव का भी आरोप है। इस समय प्रदेश में 2555 एसएमसी अध्यापक स्कूलों में कार्यरत हैं।

शिक्षा मंत्री ने 12 फरवरी को उन्हें आश्वासन दिया था की कैबिनेट सब कमेटी द्वारा फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी गई है जो की 14 तारीख की कैबिनेट में जायेगी

पर 14 की कैबिनेट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसके बाद वह 17 फरवरी के बजट से उम्मीद लगाये बैठे थे कि इसमें जरूर उनके लिये उचित फैसला होगा। लेकिन जब 17 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया इसमें एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1900 रुपए की मासिक बढ़ौतरी की गई है जबकि उनकी मांग नियमितीकरण की थी। ऐसे में एसएमसी अध्यापकों ने आक्रोशित हो 1900 रुपए मानदेय बढ़ाने का विरोध किया और 19 फरवरी से पूर्ण तौर पर कक्षाओं का बहिष्कार कर स्कूल नहीं जाने और 19 फरवरी

को सभी अध्यापक अपने परिवार सहित विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे का ऐलान कर दिया।

19 फरवरी को फिर एसएमसी अध्यापकों की शिक्षा मंत्री से भेंट हुई है जिसमें शिक्षा मंत्री ने उन्हें पूर्ण तौर पर कक्षाओं के बहिष्कार के फौसले को वापस लेने को कहा और आश्वासन दिया गया कि अगली मंत्रीमण्डल की बैठक में इस पर फैसला ले लिया जायेगा। अब शिक्षक इस इन्तजार में हैं कि शिक्षा मंत्री कब उनका क्रमिक अनशन समाप्त करवाते हैं या उन्हें पूर्ण तौर पर कक्षाओं के बहिष्कार पर जाने के लिये बाध्य करते हैं।